



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

## ओ०टी०एस० योजना का लाभ उठाये

### बकायेदार आवंटियों के लिए सुनहरा अवसर एक मुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०)

शासनादेश संख्या-8/2020/298/आठ-1-20-01विवेक/2000 दिनांक 07.02.2020 द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण से आवंटित विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों के बकाये में सम्मिलित दण्ड ब्याज की छूट प्रदान की गई है। आवासीय सम्पत्तियाँ (ग्रुप हाउसिंग सहित), समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं, केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों, स्कूल भूखण्डों एवं चैरीटेबिल संस्थानों, व्यवसायिक, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियाँ निलामी/आवंटन/अन्य किसी भी पद्धति के माध्यम से आवंटित है, इस प्रकार की समस्त सम्पत्तियों पर ओ०टी०एस० योजना लागू होगी।

### सिद्धान्त

- (1) ओ०टी०एस० योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।
- (2) आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उपरिलिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा।
- (3) आवंटी द्वारा दिये गये भुगतान सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि तक ओ०टी०एस० आधार पर आगणित ब्याज, तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।
- (4) ओ०टी०एस० योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन अन्य व्ययों जैसे - फ्री होल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इसके बावजूद भी यदि Surplus धनराशि बचती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।
- (5) यदि किसी आवंटी द्वारा स्वानुरोध अथवा किसी शासनादेश के क्रम में देयों/किश्तों का पुनर्निर्धारण कराया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में ओ०टी०एस० की गणना सम्पत्ति के आवंटन के समय निर्धारित किश्तों एवं ब्याज के अनुरूप की जाएगी।

### योजना में आवेदन हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस का विवरण निम्नवत् है

क्र० सं०	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (जी०एस०टी० सहित) (रु०)	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि	अभ्युक्ति
1.	ई०डब्ल्यू०एस० भवन/भूखण्ड	100.00	5,000.00	ओ०टी०एस० आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी।
2.	एल०आई०जी० भवन/भूखण्ड	500.00	10,000.00	
3.	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिश्रित उपयोग की सम्पत्तियों तथा व्यवसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	2,100.00	50,000.00	परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ०टी०एस० का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
4.	ग्रुप हाउसिंग	11,000.00	5,00,000.00	
5.	संस्थागत सम्पत्तियाँ	11,000.00	5,00,000.00	
6.	क्रम संख्या-3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	11,000.00	5,00,000.00	

### आवेदन हेतु समयावधि:-

1. आवेदन पत्र देने के लिये 03 माह की अवधि निर्धारित की जाती है, इस तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. ओ०टी०एस० आवेदन पत्र जमा करने की तिथि वही मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदन पत्र के साथ आपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा की कर दी गयी हों।

### आवेदन की प्रक्रिया:-

1. आवंटियों द्वारा आवेदन ऑनलाईन/ऑफलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ०टी०एस० योजना का आवास बन्धु की वेबसाईट [www.awasbandhu.in](http://www.awasbandhu.in) के होमपेज पर लिंक OTS उपलब्ध है, (जो दिनांक 06 मार्च, 2020 से क्रियाशील होगा) जिसके माध्यम से आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, इसके साथ ही आवंटी जी०डी०ए० हैल्प लाईन डैस्क पर भी आवेदन कर सकते हैं।

### भुगतान की प्रक्रिया:-

ओ०टी०एस० में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. ओ०टी०एस० गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु० 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग पर डिस्पैच (डिस्पैच का तात्पर्य एस०एम०एस०, ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किस्तों में 03 माह में जमा करना होगा अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।
2. ओ०टी०एस० गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु० 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों में 06 माह में जमा करना होगा अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।
3. अन्तिम किस्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गयी समस्त किस्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ०टी०एस० मान्य होगा अन्यथा ओ०टी०एस० निरस्त हो जायेगा। यदि सूचित की गयी किस्तें विलम्ब से जमा की जाती हैं तो विलम्ब की अवधि के लिए 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
4. डाऊन पेमेन्ट (1/3 धनराशि) के भुगतान के उपरान्त अवशेष 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
5. ओ०टी०एस० में आगणित सम्पूर्ण देय धनराशि को मांग पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एकमुश्त (UPFRONT) जमा करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि पर 02 प्रतिशत की छूट होगी।

योजना हेतु निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 06 मार्च 2020 तीन माह अवधि तक ओ०टी०एस० काउण्टर से रु० 10.00 (रुपये दस मात्र) के भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

ई-मेल : [helplinegda@gmail.com](mailto:helplinegda@gmail.com), [@gdagzb](https://www.facebook.com/gdagzb) [IG](https://www.instagram.com/gdagzb) : gdagzb

सचिव

हेल्पलाईन नं. : 0120-3342433, व्हाट्सएप : 9818988807

वेबसाईट : [www.gdaghaziabad.com](http://www.gdaghaziabad.com)

एक सुन्दर शहर ..... हमारा संकल्प

प्रेषक,

दीपक कुमार  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |  |   |
|--|---|
| 1 आवास आयुक्त,<br>30प्र0 आवास एवं विकास परिषद,<br>लखनऊ।                        | 2 उपाध्यक्ष,<br>समस्त विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश। |
| 3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,<br>समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश। |   |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2020

विषय: वन-टाईम सेटलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना) 2020 के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों तथा नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु वन टाईम सेटलमेंट योजना, 2002 के संचालन के संबंध में शासनादेश संख्या-3201/9-आ-1-02-1वि0/2000, दिनांक 12.08.02, शासनादेश संख्या-4620/9-आ-1-02-1वि0/2000, दिनांक 30.10.02 एवं शासनादेश संख्या-3367/ आठ-1-11-01 विविध/2000, दिनांक 29.11.2011 निर्गत किये गये थे। उक्त योजना की समय-सीमा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है, जो दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो गई है।

2- आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में आवासीय सम्पत्तियों तथा नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद व प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में इन सम्पत्तियों के आवंटि भुगतान में डिफाल्टर हैं, जिसके कारण प्राधिकरणों/ परिषद के बकाये की वसूली अवरूद्ध है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इन सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने एवं बकाए की वसूली हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए 'वन-टाईम सेटलमेंट' योजना-2020 निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) आवंटियों के लिए निर्धारित श्रेणी:-

- (1) ओ.टी.एस. योजना, समस्त प्रकार की आवासीय सम्पत्तियों (ग्रुप हाउसिंग सहित) पर लागू होगी, चाहे वे आवंटन पद्धति से आवंटित हों या नीलामी पद्धति से हो या अन्य पद्धति से आवंटित हों।
- (2) समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों पर ओ.टी.एस. योजना लागू होगी, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित सम्पत्तियों भी सम्मिलित होंगी।
- (3) विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चैरीटेबल संस्थाओं, आदि को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।
- (4) समस्त प्रकार की व्यवसायिक सम्पत्तियों, चाहे नीलामी द्वारा अथवा अन्य पद्धति से आवंटित हों, पर ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।
- (5) सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओ.टी.एस. योजना लागू होगी।

(ख) सिद्धान्त:-

- (1) ओ.टी.एस. योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।
- (2) आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उपरिलिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा।
- (3) आवंटी द्वारा किये गये भुगतान को सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि तक ओ.टी.एस. आधार पर आगणित ब्याज, तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।
- (4) ओ.टी.एस. योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन अन्य व्ययों जैसे-फ्री होल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इसके बावजूद भी यदि Surplus धनराशि बचती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।
- (5) यदि किसी आवंटी द्वारा स्वानुरोध अथवा किसी शासनादेश के क्रम में देयों/किस्तों का पुनर्निर्धारण कराया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में ओ.टी.एस. की गणना सम्पत्ति के आवंटन के समय निर्धारित किस्तों एवं ब्याज के अनुरूप की जाएगी।

(ग) प्रोसेसिंग फीस

क्र.सं.	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (जी.एस.टी. सहित) (₹0)	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (₹0)	अभ्युक्ति
1.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भूखण्ड	100	5,000	ओ.टी.एस. आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि, आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी। परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओ.टी.एस. का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित नहीं किया जायेगा।
2.	एल.आई.जी. भवन/भूखण्ड	500	10,000	
3.	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिश्रित उपयोग की सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	2,100	50,000	
4.	ग्रुप हाऊसिंग	11,000	5,00,000	
5.	संस्थागत सम्पत्तियाँ	11,000	5,00,000	
6.	क्रम संख्या-3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	11,000	5,00,000	

(घ) आवेदन हेतु समयावधि:-

- (1) शासनादेश निर्गत होने के 01 माह तक सभी डिफाल्टर्स को ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार (शिविर/गोष्ठी का आयोजन, होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाय) करते हुए इसके संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

- (2) तत्पश्चात ओ.टी.एस. हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 03 माह की अवधि निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) ओ.टी.एस. आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि वही मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा कर दी गयी हो।

**(ड.) आवेदन की प्रक्रिया**

- (1) आवंटियों द्वारा आवेदन आफ लाईन/ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ.टी.एस. योजना का आवास बन्धु की वेबसाईट ([www.awasbandhu.in](http://www.awasbandhu.in)) के होमपेज पर लिंक OTS2020 उपलब्ध है (जो दिनांक 06 मार्च, 2020 से क्रियाशील होगा), जिसके माध्यम से आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। आवेदकों के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने हेतु आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा हेल्प-डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी।
- (2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त गणनाशीट एवं वाँछित धनराशि जमा करने की सूचना आवंटी द्वारा दिये गये ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र व्यवहार से दी जायेगी।

**(च) आवेदन-पत्रों का निस्तारण**

ओ.टी.एस. आवेदनों का निस्तारण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 03 माह में किया जायेगा। तत्पश्चात प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में ओटीएस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तिम तिथि के बाद अनिस्तारित आवेदनों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्राधिकरण/परिषद को ह्यथी वित्तीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।

**(छ) भुगतान की प्रक्रिया**

ओ.टी.एस. में आगणित धनराशि को जमा करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

- (1) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु. 50.00 लाख तक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच ('डिस्पैच' का तात्पर्य एस.एम.एस., ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से है) होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 मासिक किस्तों में 03 माह में जमा करना होगा अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह में जमा करनी होगी।
- (2) ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रु. 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त धनराशि का 1/3 भाग, मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन में और अवशेष 2/3 भाग, 03 द्विमासिक किस्तों में 06 माह में जमा करना होगा, अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह में जमा करनी होगी।
- (3) अन्तिम किस्त हेतु निर्धारित तिथि तक यदि सूचित की गई समस्त किस्तों की धनराशि जमा कर दी जाती है, तो ओ.टी.एस. मान्य होगा अन्यथा ओ.टी.एस. निरस्त हो जाएगा। यदि सूचित की गई किस्तें विलम्ब से जमा की जाती हैं, तो विलम्ब की अवधि के लिए 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- (4) डाउन पेमेन्ट (1/3 धनराशि) के भुगतान के उपरान्त अवशेष 2/3 धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित किस्तों पर 11 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(5) ओ.टी.एस. में आगणित सम्पूर्ण देय धनराशि को मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एकमुश्त (Upfront) जमा करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि पर 02 प्रतिशत की छूट होगी।

(ज) बकाया धनराशि की वसूली

ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को देय कोई धनराशि का भुगतान यदि निर्धारित समय-सीमान्तर्गत आवंटि द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-40/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-91 के अधीन भू-राजस्व के बकाये की भांति की जाएगी।

(झ) योजना के क्रियान्वयन की मासिक प्रगति से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन आवास बन्धु द्वारा किया जाएगा तथा शासन स्तर पर आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की मासिक समीक्षा बैठकों में इस योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवास एवं विकास परिषद/प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा भी इसकी नियमित समीक्षा की जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ओ.टी.एस. योजना-2020 को प्रस्तर-2घ(1) के अनुसार सभी डिफाल्टर्स को ई-मेल/एस.एम.एस./पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इस योजना के संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
दीपक कुमार  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए हितबद्ध एवं जनसामान्य को उपलब्ध कराने तथा अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
अरूणेश कुमार द्विवेदी  
अनु सचिव

प्रेषक,

दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ:

दिनांक: 6 जून, 2020

विषय: कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01 विविध/2000 दिनांक 07.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन-टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के संचालन सम्बंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं। उक्त शासनादेश में आवेदन करने हेतु दिनांक 06.03.2020 से 03 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी, जो दिनांक 05.06.2020 को समाप्त हो गयी है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र देने की तिथि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

अनु सचिव